

मेरठ विकास प्राधिकरण

की

७६वीं बोर्ड बैठक
दिनांक २६.०६.२००६

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण की 76वीं बोर्ड बैठक दिनांक 29-06-06 का कार्यवृत्त।

* मेरठ विकास प्राधिकरण की 76वीं बोर्ड बैठक दिनांक 29-06-06 को शिविर कार्यालय, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के सभागार में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ की अध्यक्षता में पूर्वान्ह 12.00 बजे प्रारम्भ हुई। सर्वप्रथम उपाध्यक्ष द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष महोदय तथा मा० सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे:-

1-	श्री देवदत्ता आयुक्त मेरठ मण्डल गेरठ।	अध्यक्ष
2-	श्री यू०ए०१०ठाकुर उपाध्यक्ष, मे०वि०प्रा०,गेरठ।	उपाध्यक्ष,
3-	श्री मुकेश कुमार गेश्वाम, जिलाधिकारी, गेरठ।	सदस्य
4-	श्री आई०एरा०के० रिंड, सहायक नगर आयुक्त, (प्रतिनिधि-नगर आयुक्त, मेरठ)	सदस्य
5-	श्री के०एग०लाल, उप निदेशक, उद्योग मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ।	सदस्य
6-	श्री कृपाल सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम, मेरठ।	सदस्य
7-	श्री ज्ञाना०रांड, अपर निदेशक-कोषागार एवं पेशन, मेरठ।	सदस्य
8-	श्री के०जी० पुरी, उप महाप्रबन्धक (नगरीय) उ०प्र० पावर कारपोरेशन, मेरठ।	सदस्य
9-	श्री आरा०के० अयवाल, अधीक्षण अभियन्ता, आवारा एवं विकास परिषद, मेरठ।	सदस्य

३२३८
उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

11/7/06
सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

- | | | |
|-----|--|--------|
| 10- | श्री ए०के० त्यागी
सहायक नियोजक
(प्रतिनिधि-आयुक्ता एन०री०आर०)
गाजियाबाद। | सदस्य |
| 11- | श्री राजपाल कौशिक,
सहयुक्त नियोजक
(प्रतिनिधि-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग
उत्तर प्रदेश) | सदस्य |
| 12. | श्री राजकुमार यादव
शारान द्वारा नामित। | सदस्य |
| 13- | श्री श्रीनिवास जोगी
शासन द्वारा नामित। | सदस्य |
| 14- | श्री सतीश कुमार
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ। | संयोजक |

मेरठ विकास माध्यमिक बोर्ड

नवम
१९७८
सत्रित
भेरठ विकास, प्राधिकरण
भेरठ

मद सं० -१

प्राधिकरण की 75 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 24.03.06 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

प्राधिकरण की 75वीं बोर्ड बैठक दिनांक 24.03.06 के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई ।

मद सं०-२

प्राधिकरण की 75 वीं बोर्ड बैठक में पारित विभिन्न प्रस्तावों की अनुपालन आख्या ।

प्राधिकरण की 75वीं बोर्ड बैठक दिनांक 24.03.2006 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की जाये ।

मद सं०-३

प्राधिकरण का वर्ष 2005-2006 का वास्तविक एवं वर्ष 2006-2007 का प्रस्तावित आय व्ययक (बजट)

बजट पर विस्तृत चर्चा के बाद सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया । अध्यक्ष महोदय द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि सामान्यतया आडिट आपत्तियों के निराकरण की ओर प्रयाप्त ध्यान नहीं दिया जाता है । अतः निर्देश दिये गये कि बोर्ड की प्रत्येक ब्रेमासिक बैठक में आडिट आपत्तियों सम्बन्धी आख्या अवश्य प्रस्तुत की जाये जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो कि विभिन्न आडिट इकाईयों की कितनी-२ आपत्तियों का निराकरण हो चुका है और कितनी लम्बित है । तथा प्राधिकरण के लेखानुभाग को एक माह के अन्दर पूर्णतया कम्प्यूटराईज करने के निर्देश दिये ।

मद सं०-४

शताब्दी नगर आवासीय योजना हेतु सीवेज ट्रीटमैन्ट प्लान्ट के निर्माण का प्रस्ताव ।

प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक रूप से सहमति व्यक्त की गयी । मा० बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि तकनीकी विशेषज्ञ की राय लेकर सीवेज ट्रीटमैन्ट प्लान्ट के निर्माण में सही तकनीक का प्रयोग किया जाये । तकनीक का प्रस्तुतीकरण भी बोर्ड के समक्ष किया जाए । बोर्ड ने सही भी निर्देश दिये कि प्लान्ट का निर्माण विभिन्न चरणों में किया

जाये और प्लान्ट के निर्माण के लिये कोई ऋण न लिया जाये। बल्कि जितना व्यय प्लान्ट के निर्माण पर होता जाये उसे आवासीय योजना के विकास कार्यों पर भारित किया जाता रहें। माझे बोर्ड ने विचार व्यक्त किया कि प्रारम्भ में केवल एक ही प्लान्ट का निर्माण प्रारम्भ किया जाये।

मद सं०-५

गंगा नगर एवं रक्षापुरम आवासीय योजना हेतु सीवेज ट्रीटमैन्ट प्लान्ट के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव।

गद सं०-४ के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाये।

मद सं०-६

मैसर्स भारत इंजीनियरिंग एण्ड फाउण्ड्री वर्क्स हरि नगर मेरठ की रिक्त भूमि खसरा सं० 558 को समायोजन करने सम्बन्धी प्रस्ताव।

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में बोर्ड के माझे सदस्य श्री राजकुमार यादव ने विचार व्यक्त किया कि पूर्व बैठकों में निर्णय लिया गया है कि भूमि को अर्जन मुक्त करने अथवा समायोजित करने की शासन की कोई नीति नहीं है। अतः प्रस्ताव निरस्त करने योग्य है। बोर्ड के अन्य सदस्यों ने उक्त विचार से सहमति व्यक्त की और कहा कि इस सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा जो निर्णय पूर्व में लिये गये हैं उनकी पुनः पुष्टि की जाती है। अतः प्रस्ताव निरस्त किया गया एवं निर्देश दिये गये कि पूरे प्रकरण को शांसन को सन्दर्भित कर दिया जाये।

मद सं०-७

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणाओं के परिपेक्ष्य में वर्ष 2005-06 में प्राधिकरण की योजनाओं में वृक्षारोपण किये जाने के सम्बन्ध में।

उक्त प्रकरण में बैठक के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा वृक्षारोपण सम्बन्धी पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा यह असन्तोष व्यक्त किया कि प्रकरण में बिल एवं बाउचर प्रस्तुत करने सम्बन्धी पूर्व आयुक्त महोदय के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है तथा आदेश दिये गये कि सम्बन्धित बिल एवं बाउचर आदि की पत्रावली भी प्रस्तुत की जाये। प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय

योजनाओं में रोपित वृक्षों की जांच की जाये कि वर्षवार प्रत्येक योजना में कुल कितने वृक्ष रोपित किये गये तथा उनमें से कितने जीवित हैं तथा कितने अजीवित। इस जांच हेतु मा० बोर्ड द्वारा एक तीन सदस्य जांच रागिति का गठन किया गया जो निम्नवत् है :-

1- वित्त नियन्त्रक,
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ। सदस्य

2- श्री ए०के० त्यागी
राजायक नियोजक
(प्रतिनिधि--आयुत्ता एन०री०आर०) सदस्य

3- वन राज्यकांक के (राजपत्रित अधिकारी) प्रतिनिधि सदस्य

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह आदेश दिये गये कि जांच आख्या 30 दिन के अंदर प्रस्तुत की जाये।

मद सं०-८

कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता रूपये 20/- के स्थान पर रु० 150/- प्रतिमाह दिये जाने विषयक प्रस्ताव।

बोर्ड वैठक द्वारा प्रस्ताव अनुगोदित किया गया।

मद सं०-९

प्राधिकरण में कार्यरत वेतनमान कर्मचारियों को भवन किशाया भत्ता/नगर प्रतिकर भत्ता दिये जाने के प्रस्ताव।

प्रस्ताव पर मा० बोर्ड द्वारा चर्चा की गई। मा० सदस्य श्री श्रीनिवास जोगी ने विचार व्यक्त किया कि वेतनमान कर्मचारी, जिनकी लगभग 18-19 वर्षों की रोपाये हो चुकी है तथा जिनके द्वारा नियमित कर्मचारियों की तरह ही कार्य किया जा रहा है, को भी भवन किशाया भत्ता/नगर प्रतिकर भत्ता दिया जाये। मा० सदस्य श्री राजकुमार यादव ने कहा कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जहां पर यह सुविधा दी जा रही है, लाभ की स्थिति में है जबकि मेरठ विकास प्राधिकरण घाटे में चल रहा है। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि गणना करके मालूम कर लिया जाये कि इसमें प्राधिकरण पर कितना वित्तीय

जाये और प्लान्ट के निर्माण के लिये कोई ऋण न लिया जाये। बल्कि जितना व्यय प्लान्ट के निर्माण पर होता जाये उसे आवासीय योजना के विकास कार्यों पर भारित किया जाता रहें। माझे बोर्ड ने विचार व्यक्त किया कि प्रारम्भ में केवल एक ही प्लान्ट का निर्माण प्रारम्भ किया जाये।

मद सं०-५

गंगा नगर एवं रक्षापुरम आवासीय योजना हेतु सीवेज ट्रीटमैन्ट प्लान्ट के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव।

मद सं०-४ के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाये।

मद सं०-६

मैसर्स भारत इन्जीनियरिंग एण्ड फाउण्ड्री वर्क्स हरि नगर मेरठ की रिक्त भूमि खसरा सं० 558 को समायोजन करने सम्बन्धी प्रस्ताव।

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में बोर्ड के माझे सदस्य श्री राजकुमार यादव ने विचार व्यक्त किया कि पूर्व बैठकों में निर्णय लिया गया है कि भूमि को अर्जन मुक्त करने अथवा समायोजित करने की शासन की कोई नीति नहीं है। अतः प्रस्ताव निरस्त करने योग्य है। बोर्ड के अन्य सदस्यों ने उक्त विचार से सहमति व्यक्त की और कहा कि इस सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा जो निर्णय पूर्व में लिये गये हैं उनकी पुनः पुष्टि की जाती है। अतः प्रस्ताव निरस्त किया गया एवं निर्देश दिये गये कि पूरे प्रकरण को शांसन को सन्दर्भित कर दिया जाये।

मद सं०-७

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणाओं के परिपेक्ष्य में वर्ष 2005-06 में प्राधिकरण की योजनाओं में वृक्षारोपण किये जाने के सम्बन्ध में।

उक्त प्रकरण में बैठक के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा वृक्षारोपण सम्बन्धी पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा यह असन्तोष व्यक्त किया कि प्रकरण में बिल एवं बाउचर प्रस्तुत करने सम्बन्धी पूर्व आयुक्त महोदय के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है तथा आदेश दिये गये कि सम्बन्धित बिल एवं बाउचर आदि की पत्रावली भी प्रस्तुत की जाये। प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय

* भार पड़ेगा तथा यह भी निर्देश दिये कि इस सम्बन्ध में अन्य प्राधिकरणों से भी जानकारी प्राप्त कर ली जाये और समर्त सूचनाओं सहित प्रताव अगली बोर्ड बैठक में रखा जाये।

मद सं0-10

उत्तर प्रदेश स्टेट ऐक्सटाइल कारपोरेशन लि0 की मेरठ स्थित कताई गिल की भूमि को निर्धारित सर्किल रेट पर क्य किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रताव को बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया तथा अध्यक्ष महोदय हारा निर्देश दिये गये कि इस भूमि के भू-उपयोग, जो कि औद्योगिक बताया गया है को बदलने की आवश्यकता नहीं है। हवाई पट्टी के निकट स्थित होने के कारण यह भूमि अत्यन्त उपयोगी है। भूमि के कुल क्षेत्रफल (लगभग 90 एकड़) में से 2 से 5 एकड़ के चार-पाँच भूखण्ड आवश्यकतानुसार होटल निर्माण हेतु आरक्षित किये जा सकते हैं जिससे की शासन की नीति के अनुसार होटल व्यवसाय को प्रोत्साहित किया जा सके। शेष भूमि में दो विशेष आर्थिक जोन (SEZ) आई.टी एवम् जैलरी तथा जैम इन्डस्ट्री (प्रत्येक 25-25 एकड़) को स्थापित किया जा सकता है।

मद सं0-11

ग्राम रामपुर पावटी के खसरा सं0 422 पार्ट व 423 पार्ट मेरठ बागपत मार्ग पर हरित पट्टी भू-उपयोग क्षेत्र में पैद्रोल पम्प के निर्माण की स्वीकृति।

प्रताव अपूर्ण होने के कारण मा0 बोर्ड द्वारा वापस लिये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

मद सं0-12

मेरठ हापुड़ महायोजना मार्ग पर हरित पट्टी भू-उपर्योग क्षेत्र में पैद्रोल पम्प के निर्माण की स्वीकृति।

प्रताव अपूर्ण होने के कारण मा0 बोर्ड द्वारा वापस लिये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

3.3.8
उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
बौद्ध

100
1/2/00
सचिव
ग्राम नियाय प्राधिकरण
मेरठ

मद सं०-१३

विकास प्राधिकरण की योजनाओं के निकट पैरिफेरियल डबलपमेन्ट/वाह्य विकास शुल्क तथा मेरठ विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में वाह्य विकास शुल्क के सम्बन्ध में।

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में चर्चा की गई और मा० बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि इस राम्बन्ध में जिलाध्यक्ष समाजवदी पार्टी तथा रियल एस्टेट डबलपरा एरोरामेशन एवं गा० रांसद श्री मुन्नवर हुरौन द्वारा दिये गये ज्ञापनों के परिपेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण को शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये।

मद सं०-१४

प्राधिकरण के गठन वर्ष 1976 से अब तक अधीगृहीत भूमि की अध्यावधिक रिथति।

प्राधिकरण के गठन वर्ष 1976 से अब तक अधीगृहीत भूमि की अध्यावधिक रिथति का मा० बोर्ड द्वारा अवलोकन किया गया तथा निर्देश दिये गये कि नगर निगम, ग्राम सभा, सिचाई विभाग एवं सीलिंग की भूमि का भी योजनावार विवरण प्रस्तुत किया जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि जिन काश्तकारों को प्रतिकर/अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि का वितरण अवशेष है उन काश्तकारों को शीघ्रताशीघ्र भुगतान किया जाये, जिससे कि काश्तकारों में प्राधिकरण के प्रति विश्वास की भावना पैदा हो तथा अनावश्यक मुकदमेबाजी रो बचा जा सके। उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा काश्तकारों को प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त प्रतिकर धनराशि का सीधा भुगतान करने हेतु अनुमति मांगी जाने पर निर्देश दिये गये कि इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाये।

मा० अध्यक्ष ने यह भी जानना चाहा कि अधिगृहीत भूमि के किस-२ हिस्से पर प्राधिकरण के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त किये हुए हैं। यह स्थगन आदेश कव-कव से प्रभावी है और आदेशों को निरस्त करने हेतु क्या प्रयास किये गये हैं। यह भी देखा जाये कि विपक्षीण द्वारा भी इन स्थगन आदेशों का पालन किया जा रहा है या नहीं।

मा० अध्यक्ष महोदय ने यह भी जानना चाहा कि किन-२ योजनाओं में कितनी भूमि अर्जित की गयी है और अभी तक कितनी भूमि के ले-आउट तैयार किये गये हैं और ले-आउट तैयार भूमि में से कितनी भूमि निरस्तरित की जा चुकी है तथा कितनी निरस्तारण हेतु अवशेष है। अवशेष भूमि की शीघ्रताशीघ्र चलानिंग की जाये। प्रत्येक योजना में अधिगृहीत की गयी समस्त भूमि का निर्वेश भी तियोगे गये।

३२८
उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
११२/०६
सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
गैरठ

गा० भी निर्देश दिये गये कि धारा-4 एवं 6 के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रफल एवं अग्निर्णय घोषित भूमि के क्षेत्रफल में काफी अन्तर है। अतः योजनावार एवं खसरावार यह रागीक्षा की जानी आवश्यक है कि शेष भूमि को अग्निर्णय में शामिल कर्यों नहीं किया गया।

कब्जा प्राप्त करने हेतु अवशेष भूमि के सम्बन्ध में भी असन्तोष व्यक्त किया गया। सचिव, गोविंप्राठो को निर्देश दिये गये कि भूमि अध्याप्ति कार्यालय से रागपक्ष कर एक माह में प्रत्येक योजना में अवशेष भूमि का कब्जा प्राप्त करें तथा अनुपालन आख्या आगामी बोर्ड में प्रस्तुत करें।

अध्यक्ष गहोदय ने यह भी निर्देश दिये कि अवैध कब्जों के अन्तर्गत अधिगृहीत भूमि का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाये तथा योजनावार कार्यक्रम निर्धारित कर भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जाये तथा अनुपालन आख्या आगामी बोर्ड वैठक में रखे।

गा० अध्यक्ष ने जिला प्रशासन से प्रबन्धन/रखरखाव हेतु प्राप्त ग्रामीण सीलिंग/शहरी सीलिंग की भूमि का ब्यौरा प्रस्तुत किये जाने और रथन निरीक्षण कराकर उक्त भूमि की गाटावार भौतिक स्थिति के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। सीलिंग भूमि की सुरक्षा हेतु काटेदार तार लगाये जाने तथा प्रत्येक कब्जा प्राप्त भूमि पर प्राधिकरण के बोर्ड लगाये जावें।

328. १८८५
उपाध्यक्ष विवाहारण
सचिव
भैरव विवाह प्राधिकरण
गोव

अनुपूरक प्रस्ताव ।

अनुप्राक गद ४० ।

नई पर्यटन नीति रामबन्धित शासनादेश संख्या 984/41-06-180/2006 पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 22 मई, 2006 को प्राधिकरण में अंगीकृत करने के सम्बन्ध में।

पाठ वोर्ड द्वारा जारी उक्त शासनादेश को अंगीकृत किया गया एवं निर्देश दिए गए कि छोटल व्यवसाय हेतु भूमि का चिन्हीकरण कर अधिग्रहण कार्यवाही की जाए।

अनुप्रक भद्रा०-२

प्राधिकरण की योजनाओं में ७०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद को प्राथमिक पाठशाला के लिये निःशल्क गुण दिये जाने के सम्बन्ध में।

माठ वोर्ड द्वारा प्रतताव अनुगोदित किया गया। माठ वोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रत्येक आवारीग गोजना में पुलिस थाना/चौकी, अग्निशमन विभाग एवं पोरट आफिस के लिए भी निःशुल्क गूगि का प्राविधान किया जाये तथा पुलिस विभाग से अनुरोध किया जाये कि पुलिस थाना/चौकी का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र पूरा कर वहां पर आवश्यक रटाफ शीघ्र रैंगात कर दिया जाये ताकि आवंटियों में सुरक्षा की भावना पैदा हो सके। इरी प्रकार का अनुरोध अग्निशमन विभाग तथा डाक विभाग से भी किया जाये। सरकारी अपताल एवं नियुत रावरटेशन के लिए गूगि का प्राविधान करने के भी निर्देश दिये गये।

अनुपूरक मद रांगोली

प्राधिकरण की योजनाओं में ग्रुप हाउसिंग के लिये भूखण्डों का आरक्षण।

ग्रौट द्वारा प्रताव को अनुमोदित किया गया तथा गिर्देश दिये गये कि इसी प्रकार विल्डरी के लिए सहकारी आवारा रामितियों के लिए एवं रीनियर रीट्रिजन के लिए भी भूमि आरक्षित की जाये। इस रामबन्ध में विस्तृत प्रस्ताव ग्रौट के रामका परतत किया जावें।

~~3x35~~

१८८८
११२५०६
संविल
एक विद्यार्थी प्राधिकरण
प्रैद

अनुपूरक मद सं0-4

नेशनल बिल्डिंग कोड में सुरक्षित निर्माण सम्बन्धी नये प्राविधानों को प्राधिकरण की भवन उप-विधियों में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

वोर्ड द्वारा प्रताव रार्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अनुपूरक मद सं0-5

प्राधिकरण की समस्त आवासीय योजनाओं में अनुरक्षण शुल्क समय से न जमा करने पर दण्ड ब्याज न लगाने हेतु प्रस्ताव।

प्रताव मा० वोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिये गये कि
यह रार्वसम्मति केवल 30.09.2006 तक दी जाये। इसके बाद कोई समयवृद्धि न दी जाए।

अनुपूरक मद सं0-6

श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, वाहन चालक को दिल का दौरा पड़ने के कारण हार्ट सर्जरी पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के समबन्ध में प्रस्ताव।

प्रताव मा० वोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

328
11/10/06
सचिव
भैरव विकास प्राधिकरण

अनुपूरक मद रां०-७

गेरठ विकास प्राधिकरण की वेद व्यासपुरी योजना के अन्तर्गत सी०आर०पी०एफ० बटालियन की रथापना हेतु आंवटित 25 एकड़ भूमि पर कब्जा हस्तगत करते समय देय लीजरैन्ट की धनराशि विभाग द्वारा अदा न कर पाने के फलस्वरूप, देय व्याज की धनराशि की मुक्ति विषयक प्रस्ताव।

प्रस्ताव मा० बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

अनुपूरक मद रां०-८

प्राधिकरण की राष्ट्रिय से अनाधिकृत कब्जे हटाने एवं अवैध निर्माण कार्यों पर अंकुश लगाने हेतु प्राधिकरण में पुलिस चौकी की स्थापना।

प्रस्ताव मा० बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

अध्यक्ष गहोदय द्वारा बैठक के दौरान निम्न निर्देश भी दिये गये :-

क०सं०	जारी निर्देश	कार्यवाही
1.	2.	3.
1.	अध्यक्ष गहोदय द्वारा महा नगर में यातायात की रागरण पर चिन्ता व्यक्त की गई तथा निर्देश दिये गये कि शहर की ट्रेफिक समरण्या को दूर करने के लिये एक टाई-वाउंड रस्टेली कराई जाये ताकि यातायात व्यवरण्या रुधारी जा सके।	नगर-निगम एवम् मेरठ विकास प्राधिकरण
2.	एन०री०आर० गे० गेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे की सर्वे की स्थिति से अवगत कराया जाये।	मुख्य नगर नियोजक, एम०डी०ए०
3.	मैट्रो ट्रेन नोयडा तथा गाजियाबाद तक स्वीकृत हो चुकी है उसको मेरठ तक लाये जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जाये। दिल्ली गेरठ के मध्य EMU ट्रेन	मुख्य नगर नियोजक, एम०डी०ए०

3/3

11

1/2/06
सचिव
गेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

	चलाने पर भी विचार हो सकता है जो दिल्ली-मेरठ के बीच में तीन-चार चक्रकर लगा सके। चूंकि मेरठ एन०सी०आर० योजना के अन्तर्गत आता है। इसके लिये सरकारी रांथा "राईट" से सर्व करा लिया जाये कि मेरठ के लिये गैट्रो रेल, मौनो रेल अथवा रकाई रेल में से कौन सी ठीक रहेगी। ताकि दिल्ली-मेरठ का सफर 40-45 मिनट में किया जा सके। यह कार्य बी०ओ०टी० अथवा पी.पी.पी. के आधार पर कराये जाने पर विचार किया जाये।	
4.	अध्यक्ष महोदय द्वारा मेरठ रिंग रोड के बारे में जानकारी चाही गई जिसमें रायिव, एम०डी०ए० द्वारा अवगत कराया गया कि रिंग रोड हेतु भूमि अर्जन का प्ररताव ए०डी०ए०-एल०ए० / शासन को भेजा गया है परन्तु प्रस्ताव पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि चूंकि गहानगर की यातायाद व्यवस्था के लिए रिंग रोड अत्याधिक गहत्पूर्ण है अतः एक आ०शा० पत्र प्रयुक्त रायिव को भेजा जाये।	प्रभारी अधिकारी, भूमि-अर्जन, एम०डी०ए० एवं अपर जिलाधिकारी, भूमि अध्याप्ति, मेरठ।
5.	मेरठ शहर में नौराही का सौन्दर्यकरण भी कराया जाये।	उपाध्यक्ष, एम०डी०ए०
6.	मेरठ गहायोजना-2021 के आधार पर शहर में रीवरेज, पेयजल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति यातायात एवं जल निकारी हेतु अलग-2 योजनाये बनाई जाये।	नगर-निगम एवं मेरठ विकास प्राधिकरण
7.	मेरठ में री०एन०जी० एवं पी०एन०जी० हेतु स्टेडी कराई जाये। इसके बाद निजी निवेशकर्ताओं को आमन्त्रित किया जाये।	मुख्य नगर नियोजक, एम०डी०ए०
8.	महायोजना के अन्तर्गत जिन अनाधिकृत कालोनियों का निर्माण किया जा रहा है उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाये तथा इससे बोर्ड को भी अवगत कराया जाये।	सचिव, एम०डी०ए०
9.	अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि ट्रैमारिक बोर्ड वैठक अवश्य की जाये तथा ट्रैमारिक भौतिक गित्तीय प्रगति से अवगत कराया जाये।	सचिव, एम०डी०ए०
10.	रालक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक लाईटे (रोलर लाईटे), वरा शैल्टर की व्यवस्था की जाये तथा रोड-डिवाई ड्रो को सुधारा जाये।	उपाध्यक्ष, एम०डी०ए०

11.	शहर में बुहद वृक्षारोपण किया जाये।	एम०डी०ए०
12.	चौराठो एवं टायलेटो का सौन्दर्यकरण कराया जाये तथा ओवर हैड साइनेज लगवाएं जाये।	एम०डी०ए०
13.	बैठक में मौहिददीनपुर एवं अन्य इलाकों में अवैध कालोनियों एवं अवैध निर्माणों की स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की गयी एवं इसके लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।	सचिव, एम०डी०ए०

आध्यक्ष एवं अन्य मात्र सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक का समापन किया गया।

५८
(देवदत्त)

अध्यक्ष

मे० वि० प्रा०, मेरठ।

३८२
(यू०एन०ठाकुर) उपाध्यक्ष
उपाध्यक्ष, बैठक विभाग सचिवकरण
मे० वि० प्रा०, मेरठ।

८८८ ११/०६
(सतीश कुमार)

सचिव
बैठक विभाग, प्राधिकरण
मे० वि० प्रा०, मेरठ।

कार्यवाही

दिनांक : ४ -८ -२००७